भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 25 का उत्तर

आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनों का निर्माण

***25. श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के भीतर पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली कितनी नई रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं;
(ख) इन लाइनों का निर्माण कब आरंभ हुआ और वर्ष-वार कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइनों का निर्माण/वर्गीकरण किया गया है;
(ग) इन रेल लाइनों के निर्माण के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया/वर्गीकृत किया गया है; और
(घ) सरकार की इन रेल लाइनों के निर्माण को कब तक पूरा करने की योजना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनों के निर्माण के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री केसिनेनी शिवनाथ के तारांकित प्रश्न सं. 25 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं को राज्य-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत तथा निष्पादित किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

बहरहाल, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 17 नई लाइनें, जिनकी कुल लंबाई 1,935 किलोमीटर है और लागत 26,292 करोड़ रुपए है, योजना/अनुमोदन/निष्पादन के चरण में हैं, जिसमें से 184 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, 5,530 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

नई लाइन परियोजनाओं पर राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों और रेलवे की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है। ये परियोजनाएं चालू परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मार्गों पर निर्भर करते हुए लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्क, अनुपलब्ध कडियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं जिसमें पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता भी शामिल है।

आंध्र प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्व तट रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। परियोजनाओं की लागत, व्यय, परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

2014 से, भारतीय रेल में परियोजनाओं हेतु निधि आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है और तदनुरूप इनकी कमीशनिंग भी की गई है।

s.k

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	363 किलोमीटर	72.6 किलोमीटर प्रतिवर्ष	-
2014-24	1,510 किलोमीटर	151 किलोमीटर प्रतिवर्ष	2 गुना से अधिक

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से स्थित अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	बजट परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत वार्षिक आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-2014	886 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-2024	8,406 करोड़ रु.	9 गुना से अधिक

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना/निष्पादन राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है तथा ये सभी कारक परियोजना/ओं के निष्पादन और समापन समय को प्रभावित करते हैं।

****

s.k